

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रतिकर ने प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली शुक्रवार जनवरी 19, 1973/पौष 29, 1894

No. 25]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1973/PAUSA 29, 1894

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ पर प्रकाशित है कि इसे कि वह अलग-अलग रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

*New Delhi, the 19th January 1973*

**S.O. 34(E)/18FB/IDRA/73.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 727(E)/18A/IDRA/72, dated the 29th November, 1972, the management of the industrial undertaking known as Messrs. Containers and Closures, Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 28th November, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, metallurgical industries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 2/17/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

का०आ० 34 (अ)/18 ए०बी०/आई०डी०आर० ए०/ 73.—यस: भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 727 (ई)/18 ए०/आई०डी०आर० ए०/ 72, तारीख 29 नवम्बर, 1972 द्वारा मैमर्स कन्टिनेंटेड एण्ड डीजर्स, लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के अधीन 28 नवम्बर, 1977 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह गमावान्त हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, अनुसूचित उद्योग अर्थात् धातुकामिक उद्योग, में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 ख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, मंत्रालय के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, उनमें भिन्न, (जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूति दायित्वों से संबंधित हैं) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हों, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधि-कार, निष्पाधिकार, साध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे।

[सं० फा० 2/17/72—मी० यू० यी०]

दिनेश किशोर मुखर्जी, संयुक्त सचिव।